RESEARCH PAPER | Commerce | Volume : 6 | Issue : 3 | March 2016 | ISSN - 2249-555X | IF : 3.919 | IC Value : 74.50

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में लघु उद्योगों की स्थिति

KEYWORDS

डॉ.एच.एस.भाटिया	सत्यदेव त्रिपाठी
सहायक प्राध्यापक(वाणिज्य) शास.नेहरू,स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ़,जिला –राजनांदगांव(छ.ग.)	सहायक प्राध्यापक(वाणिज्य) शास.रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय घुमका, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

ABSTRACT छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला राजनांदगांव जिला औद्योगिक दृष्टि से *'B' (Backword)* श्रेणी का जिला है । यह मुख्यतःग्रामीण जनसंख्या और आदिवासी बाहुल्य वाला जिला है । वर्तमान में जिले में सूक्ष्म लघु, मध्यम,वृहद एवं मेगा पांचो श्रेणियों की औद्योगिक इकाइयों का परिचालन हो रहा है । मेरे अध्ययन का मुख्य केन्द्र जिले में लघु उद्योगों की स्थापना की प्रवृत्ति,इनमें वर्षवार पूंजी विनियोजन एवं रोजगार उपलब्धता की स्थिति का आकलन कर लघु उद्योगों की स्थिति ज्ञात करनी है ताकि भविष्य में जिले के आर्थिक विकास में इन उद्योगों के योगदान को चिन्हांकित किया जा सके ।

प्रस्तावना :–

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये अत्यन्त उपयोगी लघु उद्योगों नें देश में बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न बेरोजगारी और आर्थिक विषमता, गांवो में शहरों की ओर पलायन रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । भारतीय लघु उद्योग का अतीत बड़ा स्वर्णिम रहा है । प्राचीन भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित सूतीवस्त्र,बहुमूल्य धातुकर्म, जवाहरात के काम,काष्ठ नक्काशी आदि विश्वविख्यात थे । प्राचीन भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योगों को उस समय उत्पादित सभी वस्तुओं में निपुणता प्राप्त थी । अतीत में भारत को विश्वव्यापार का सिरमौर बनाने वाली लघु उद्योग इकाइयां अपनी उत्कृष्ठ उत्पादन कौशल कला की पुनरावृत्ति आज भी कर सकते है । साथ ही निर्यात संवर्धन, विश्वव्यापार में प्रभुत्व,रोजगार उत्पादन आदि प्रबल चुनौतियों का सामना लघुउद्योगों के माध्यम से सहजता के साथ किया जा सकता है । अध्ययन का उदेदश्य :– मेरे द्वारा 'छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में लघुउद्योगों की स्थिति' विषय को शोध के लिये चयन करने के प्रमुख उदेश्य निम्न है :–

(1) राजनांदगांव जिले के औद्योगिक परिदृश्य में लघु उद्योगों की स्थिति का पता लगाना ।
(2) लघु उद्योगों द्वारा दिये जाने वाले रोजगार उत्पादन की वर्तमान स्थिति एवं भावी संभावनाओं का पता लगाना ।
(3) लघुउद्योगों के स्थापना एवं संचालन में आने वाली समस्याओं का पता लगाना एवं उसके निराकरण हेतु उपाय प्रस्तुत करना ।

अध्ययन की सीमायें :–

(1) मेरा अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक समंको पर आधारित है और उपलब्ध समंको की विश्वसनीयता,प्रमाणिकता,सत्यता और सार्थकता की पूर्णरूपेण जांच करने के उपरान्त ही इसका उपयोग किया गया है ।
(2) अध्ययन में प्राथमिक समंको का संकलन औद्योगिक सूत्री में से प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र से 05–05 लघु उद्योगों का दैव–निदर्शन पद्धति द्वारा चयन कर किया गया है ।
(3) प्राथमिक समंक केवल राजनांदगांव जिले के लघु उद्योगों से संबंधित है एवं ये संमक केवल वर्ष 2000–01 से 2012–13 के हैं ।

हमारे देश में करोड़ों ऐसे लोग है जिनके जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकतायें–रोटी,कपडा और मकान की भी पूर्ति नहीं हो पाती । अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब । इस आर्थिक विषमता की गहरी खाई को पाटना तभी संभव है जब गरीब भी अपनी शारीरिक ,मानसिक और आर्थिक क्षमतानुसार उद्यमिता को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करें । ऐसा केवल लघुउद्योगों पर आधारित आर्थिक संरचना से ही संभव है ।

मेरा अध्ययन 1 नवंबर , 2000 से पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरान्त राजनांदगांव जिले में लघुउद्योगों के विकास,इनमें पूंजी विनियोजन एवं रोजगार उपलब्धता पर आधारित है, जो कि निम्नतालिका से स्पष्ट हो रहा है :–

तालिका कमांक 1
जिले में लघुउद्योगों की स्थापना की वर्षवार प्रवृत्ति

वर्ष	स्थापित इकाइयां	पूंजी विनियोजन (लाख रू में)	रोजगार उपलब्धता
2000–01	301	380.07	743
2001–02	52	31.34	259
2002–03	168	172.90	517
2003–04	31	157.13	361
2004–05	42	297.67	362
2005–06	47	497.45	396
2006–07	32	889.49	407
2007–08	42	133.92	466
2008–09	54	218.14	527
2009–10	45	1251.99	963
2010–2011	60	1470.47	677
2011–2012	158	246.24	606
2012–2013	64	1281.38	471
	1096	7028.19	6755

स्रोतः जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, राजनांदगांव (छ.ग.)

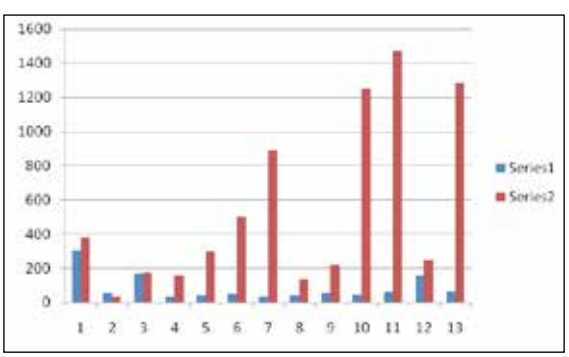

चित्र कमांक – 01 स्थापित इकाई और पूंजी विनियोजन

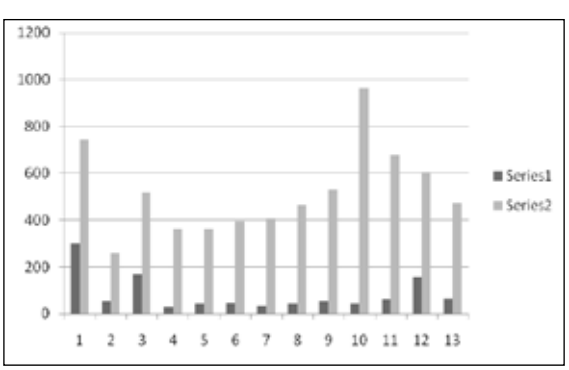

चित्र कमांक – 02 स्थापित इकाई और रोजगार उपलब्धता

उपरोक्त तालिका कमांक 1 के विश्लेषण से यह ज्ञात हो रहा है कि राज्य निर्माण

Volume : 6 | Issue : 3 | March 2016 | ISSN - 2249-555X | IF : 3.919 | IC Value : 74.50

के पश्चात वर्ष 2000–01 में सर्वाधिक लघु उद्योग इकाइयां स्थापित हुई जिनकी संख्या 301 है और इनमें पूंजी विनियोजन 380.07 लाख रूपये थी । बाद के वर्षो में स्थापित इकाइयों की संख्या तो कम हुई लेकिन आनुपातिक रूप से विनियोजित पूंजी बढ़ती ही गई । वर्ष 2006–07 में स्थापित लघु इकाइयां 32 और विनियोजित पूंजी 889.49 लाख रूपये , 2009–10 में स्थापित इकाइंया 45 और विनियोजित राशि 1251.99 लाख रूपये वर्ष 2010–11 में स्थापित इकाइंया 60 और विनियोजित राशि 1470.47 लाख रूपये और वर्ष 2012–13 में पंजीकृत इकाइयां 64 और इनमें विनियोजित राशि 1281.38 लाख रूपये रही । इस प्रकार प्रति इकाई विनियोजित राशि में वृद्धि की प्रवृत्ति दिख रही है ।

इसी प्रकार राज्य निर्माण के बाद के 13 वर्षो (2000–01 से 2012–13) में जिले में कुल 1096 लघु उद्योग स्थापित हुये एवं इनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या 6,755 है अर्थात प्रति उद्योग औसत नियोजन 06 है । वर्षवार रोजगार उपलब्धता में वर्ष 2000–01, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में क्रमशः 743, 963, 677 एवं 606 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में तुलनात्मक रूप से अन्य वर्षो से बेहतर रहे है । लेकिन उद्योगों की संख्या के आधार पर औसत नियोजन की स्थिति में वर्ष 2009–10, 21.4 के आधार पर श्रेष्ठ वर्ष रहा है । इसके पश्चात वर्ष 2003–04, 2007–08 एवं 2010–11 में औसत नियोजन क्रमशः 11.65, 11.09 एवं 11.28 रही है जबकि सबसे कम औसत नियोजन वर्ष 2000–01 में 2.47 रही है ।

निष्कर्ष :–

(1) राजनांदगांव जिले में प्रतिवर्ष औसत 84 लघु उद्योग स्थापित हुये हैं और इनमें औसत पूंजी विनियोजन (वार्षिक) 540.63 लाख रूपये हुई है जो कि संतोषजनक स्थिति नही है ।
(2) इसी प्रकार जिले के लघुउद्योगों में प्रति उद्योग औसत 06 व्यक्तियों को रा. `जगार उपलब्ध होने की स्थिति में राजनांदगांव जिले के लघुउद्योग, जिले की बेरोजगारी एवं अर्द्धबेरोजगारी को किस सीमा तक दूर कर पायेंगे,यह विचारणीय तथ्य है ।
(3) इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राजनांदगांव जिले में लघु उद्योगों की स्थिति एवं विकास की निरंतरता संतोषप्रद नहीं है । लघु उद्योगों के विकास के लिये जिले में शासन – प्रशासन को अतिरिक्त रूचि लेने की आवश्यकता है ।

संदर्भ ग्रंथ :–

(1) छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग, रायपुर का प्रशासकीय प्रतिवेदन, वर्ष 2001–01 से 2012–13 तक
(2) माथुर डॉ0 बी0एल0,लघुउद्योग वित्त, अर्जुन पब्लिसिंग हाऊस नईदिल्ली
(3) माथुर डॉ0 बी0एल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अर्जुन पब्लिसिंग हाऊस नईदिल्ली
(4) त्रिपाठी प्रो0 मधुसूदन,लघुउद्योग : महत्व एवं समस्यायें, राधा पब्लिकेशन्स, नईदिल्ली